



2026: AHC: 3325

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-41591 सन् 2025

गोविन्द सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता :- जितेन्द्र कुमार, केशव हरि दीक्षित, पुरुषोत्तम दीक्षित

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता :- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य –प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए० जी० ए० श्री राजेश कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्त –आवेदक की ओर से, पुलिस थाना –साइबर क्राइम, जनपद-अलीगढ़ में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66- सी एवं 66- डी के अंतर्गत पंजीकृत वाद अपराध संख्या 101 सन् 2025 में जमानत पर उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त –आवेदक निर्दोष है तथा उसे उक्त वाद अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कुछ विलंब से दर्ज की गई है, जिसके लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विवेचना अधिकारी आवेदक को उक्त अपराध से जोड़ने हेतु उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य एकत्रित नहीं कर सके। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिपोर्ट में अंकित नहीं है तथा उसका नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है तथा कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान वाद में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा आवेदक से किसी प्रकार की अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान वाद में आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका अथवा उद्देश्य आरोपित नहीं किया गया है। आवेदक दिनांक 27.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। जमानत पर उन्मोचित किए जाने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से पलायन करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान ए० जी० ए० ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया , किन्तु आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों , आरोपों की प्रकृति , दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता तथा सहायक साक्ष्यों की प्रकृति , साक्षियों से छेड़छाड़ की युक्तिसंगत आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए , किंतु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना , जमानत का एक प्रकरण निर्मित होता है।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित वाद-अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक , **गोविन्द सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभु को निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जमानत पर उन्मोचित किया जाए:

- i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/ उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक एवं हर तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न कर दी जाए।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्रता होगी।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

7 जनवरी, 2026

पी के एस